PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 043
दि. 12.06.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

नारी शक्ति का वंदन

गुजरात सरकार

32+ करोड़ महिलाओं के जन-धन खाते खुले

3+ करोड़ महिलाएं बनीं लखपति दीदी

₹16+ लाख करोड़ के मुद्रा लोन महिलाओं को, उद्यमिता को मिला बल

12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 'लखपति दीदी' और 'मुद्रा लोन' जैसी पहलें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर विकसित भारत की नींव मजबूत कर रही हैं।

- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक संदेश: 'गृहिणी नहीं, राष्ट्र निर्माता' घरेलू श्रम का न्यूनतम मूल्य ₹30 हजार प्रतिमाह माना जाए

नई दिल्ली। भारतीय समाज में वर्षों से घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने वाली महिलाओं के योगदान को अक्सर नैतिक और सामाजिक सम्मान तो मिलता रहा है, लेकिन उनके श्रम का आर्थिक मूल्यांकन शायद ही कभी गंभीरता से किया गया हो। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाले फैसले में इस सोच को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कहा कि घर संभालने वाली महिलाओं को केवल "गृहिणी" या "होममेकर" के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें "राष्ट्र निर्माता" के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि परिवार, समाज और देश के निर्माण में महिलाओं की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि उनके घरेलू कार्यों और देखभाल संबंधी सेवाओं का आर्थिक मूल्य निर्धारित करते समय उसे कमतर नहीं आंका जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल एक कानूनी निर्णय भर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे महिलाओं के अवैतनिक श्रम को सामाजिक और आर्थिक पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। अदालत ने कहा कि जब किसी दुर्घटना, मृत्यु या मुआवजे से जुड़े मामले में गृहिणी के योगदान का मूल्यांकन किया जाए, तो उसकी घरेलू सेवाओं का न्यूनतम मूल्य 30 हजार रुपये प्रतिमाह माना जाना चाहिए। इससे पहले ऐसे मामलों में प्रायः न्यूनतम मजदूरी के आधार पर आय का अनुमान लगाया जाता था, जिसे अदालत ने वर्तमान सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप पर्याप्त नहीं माना।

यह फैसला जस्टिस Sanjay Karol और N. K. Singh की पीठ ने सुनाया। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि घर के भीतर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य केवल भोजन बनाने तक सीमित नहीं होते। वे परिवार के संपूर्ण संचालन, बच्चों के पालन-पोषण, बुजुर्गों की देखभाल, घरेलू प्रबंधन, भावनात्मक सहयोग और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण जैसी अनेक जिम्मेदारियां निभाती हैं। इन कार्यों का प्रभाव केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास पर भी पड़ता है।

अदालत ने कहा कि यदि किसी परिवार से गृहिणी की भूमिका अचानक समाप्त हो जाए, तो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए कई अलग-अलग लोगों और सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में यह मानना कि गृहिणी कोई आर्थिक

योगदान नहीं देती, वास्तविकता से बहुत दूर है। न्यायालय ने कहा कि घरेलू कार्यों का मूल्यांकन केवल बाजार आधारित आय के दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका सामाजिक और मानवीय महत्व कहीं अधिक व्यापक है।

यह महत्वपूर्ण फैसला एक सड़क दुर्घटना मुआवजा मामले की सुनवाई के दौरान आया। मामला उस महिला से संबंधित था जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके पति शिशुपाला और तीन बच्चों ने मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान यह प्रश्न उठा कि एक गृहिणी के योगदान का आर्थिक मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया जाए। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टिप्पणी करते हुए महिलाओं के घरेलू श्रम को लेकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया।

पीठ ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अक्सर गृहिणी को परिवार के कमाने वाले सदस्य पर निर्भर माना जाता है, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। अदालत ने कहा कि परिवार का दैनिक जीवन, उसकी व्यवस्था, बच्चों का विकास और घरेलू संतुलन काफी हद तक गृहिणी पर निर्भर करता है। इसलिए उन्हें आश्रित मानना विडंबनापूर्ण है। न्यायालय ने उम्मीद जताई कि भविष्य में "गृहिणी" शब्द का उपयोग उनके योगदान को कम करके आंकने के बजाय सम्मान और गरिमा के साथ किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि महिलाओं के योगदान को मान्यता देने की दिशा में समाज ने कुछ प्रगति जरूर की है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। अदालत ने कहा कि घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों को लंबे समय तक स्वाभाविक जिम्मेदारी मान लिया गया, जिसके कारण उनके आर्थिक महत्व को पर्याप्त पहचान नहीं मिल सकी। जबकि वास्तविकता यह है कि परिवारों और अर्थव्यवस्था के सुचारु संचालन में इन कार्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

फैसले में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री Cecil Pigou के विचारों का भी उल्लेख किया गया। अदालत ने कहा कि विभिन्न अध्ययनों के अनुसार महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का भारत की अर्थव्यवस्था में अनुमानित 15 से 17 प्रतिशत तक योगदान माना जाता है। इसके बावजूद यह योगदान राष्ट्रीय आय और आर्थिक आंकड़ों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। न्यायालय ने संकेत दिया कि इस प्रकार का श्रम देश की आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण आधार है और इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने विशेष रूप से "मानव पूंजी निर्माण" की अवधारणा पर भी जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि महिलाओं की भूमिका केवल बच्चों को जन्म देने तक सीमित नहीं है। वे बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यही बच्चे आगे चलकर देश की मानव पूंजी बनते हैं और राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो घरों में किया जाने वाला कार्य प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों, बीमा दावों और अन्य कानूनी विवादों में महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उन परिवारों को भी राहत मिल सकती है, जिनकी महिला सदस्य घर संभालने की जिम्मेदारी निभा रही थीं और जिनके योगदान का आर्थिक मूल्यांकन पहले अपेक्षाकृत कम किया जाता था।

सामाजिक दृष्टि से भी इस निर्णय को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से महिला अधिकारों से जुड़े संगठन यह मांग करते रहे हैं कि घरेलू श्रम को औपचारिक आर्थिक मान्यता दी जाए। उनका तर्क रहा है कि यदि गृहिणियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का बाजार मूल्य जोड़ा जाए, तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उसी दिशा में एक मजबूत न्यायिक संदेश के रूप में देखी जा रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला केवल मुआवजे की गणना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर सकता है। इससे घरेलू कार्यों को लेकर सम्मान और जागरूकता बढ़ने की संभावना है। साथ ही यह संदेश भी जाएगा कि घर के भीतर किया जाने वाला श्रम अदृश्य नहीं है, बल्कि वह परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र निर्माण केवल कार्यालयों, कारखानों और संस्थानों में नहीं होता, बल्कि घरों के भीतर भी होता है, जहां लाखों महिलाएं बिना किसी वेतन, पद या पहचान की अपेक्षा के परिवारों को संभालती हैं। न्यायालय ने इसी योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें "राष्ट्र निर्माता" की संज्ञा दी है, जो भारतीय न्यायिक इतिहास में महिलाओं की भूमिका को नई दृष्टि से देखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

राज्यसभा चुनाव में भाजपा का दबदबा बरकरार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की छह सीटों के परिणाम घोषित

जयपुर/भोपाल। राज्यसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलकों में कई दिनों से चल रही चर्चाओं और आरोप-प्रत्यारोप के बीच गुरुवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्यसभा सीटों के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए गए। दोनों राज्यों में निर्धारित मतदान तिथि 18 जून थी, लेकिन किसी भी सीट पर मुकाबले की स्थिति नहीं बनने के कारण निर्वाचन आयोग ने सभी विजयी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। परिणामों के अनुसार छह सीटों में से पांच पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई।

राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे इन चुनावों में राजस्थान की तीन और मध्य प्रदेश की तीन सीटों पर निर्वाचन होना था। दोनों राज्यों में संख्या बल पहले से ही लगभग स्पष्ट तस्वीर पेश कर रहा था, जिसके चलते अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि परिणामों में कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिलेगा। अंततः वही हुआ और अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया।

हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन रद्द होने को लेकर विवाद ने चुनावी प्रक्रिया को राजनीतिक बहस का विषय बना दिया। कांग्रेस ने इस मामले में गंभीर सवाल उठाए और निर्वाचन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, जबकि भाजपा ने सभी आरोपों को निराधार बताया। मामला न्यायिक स्तर तक पहुंचने के बावजूद निर्वाचन प्रक्रिया अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ी और परिणाम घोषित कर दिए गए। राजस्थान में चुनावी तस्वीर शुरुआत से ही काफी स्पष्ट मानी जा रही थी। यहां राज्यसभा की तीन सीटें रिक्त हो रही थीं, क्योंकि मौजूदा सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। विधानसभा में दलों की संख्या के आधार पर भाजपा दो सीटें और कांग्रेस एक सीट जीतने की स्थिति में थी। इसी कारण यहां चुनावी मुकाबला अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की क्रॉस वोटिंग या राजनीतिक टकराव की आशंका नहीं दिखाई दी। भाजपा ने राजस्थान से वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया था। दोनों उम्मीदवारों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने मौजूदा सांसद नीरज डांगी पर एक बार फिर भरोसा जताया और उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने में सफलता हासिल की। नीरज डांगी का निर्विरोध निर्वाचन कांग्रेस के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी राज्यसभा में अपनी उपस्थिति बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया अपेक्षाकृत सहज रही, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति अधिक चर्चा का विषय बनी रही। यहां राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होना था और भाजपा ने रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ तथा महेश केवट को मैदान में उतारा था। भाजपा के पास विधानसभा में इतना संख्या बल मौजूद था कि उसके दो उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। तीसरी सीट को लेकर राजनीतिक रणनीति अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी।

कांग्रेस ने इस सीट के लिए वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। उनके चुनाव मैदान में आने के बाद मुकाबले की संभावना बनी थी। हालांकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और कानूनी कारणों का हवाला देते हुए उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। इसी निर्णय ने पूरे चुनाव को विवादों के केंद्र में ला दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी और इससे लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है। पार्टी नेताओं ने निर्वाचन आयोग और भाजपा के बीच मिलीभगत के आरोप भी लगाए। दूसरी ओर भाजपा ने कहा कि नामांकन रद्द होने का निर्णय पूरी तरह नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार लिया गया है तथा इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक भूमिका नहीं है।

मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर उठे विवाद के बाद मामला न्यायालय तक पहुंच गया और इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। इसके बावजूद चुनावी प्रक्रिया पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ा और भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। इस प्रकार मध्य प्रदेश की तीनों सीटें भाजपा के खाते में चली गईं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन परिणामों से राज्यसभा में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थिति और मजबूत होगी। हालांकि कुल संख्या में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन भाजपा ने उन राज्यों में अपनी संगठनात्मक और राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है जहां वह पहले से मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस के लिए राजस्थान से एक सीट बरकरार रखना महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और एक भी सीट हासिल न कर पाने से पार्टी को राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी अब इस मुद्दे को राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर आगे बढ़ाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। राज्यसभा चुनावों के ये परिणाम ऐसे समय सामने आए हैं जब राष्ट्रीय राजनीति में आगामी रणनीतियों को लेकर विभिन्न दल सक्रिय हैं। राज्यसभा में संख्या बल किसी भी सरकार और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत फैसलों पर उच्च सदन की भूमिका निर्णायक होती है।

संपादकीय

भाखड़ा का जल स्तर

हमारे नीति-नियंता आमतौर पर तब जागते हैं जब समस्या सिर पर आ जाती है। यदि समय रहते तंत्र, सजगता और सतर्कता से आसन्न संकट को महसूस करते हुए तत्काल रणनीति बनाकर कार्रवाई करता है, तो जन-धन की हानि को टाला जा सकता है। निस्संदेह, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी ने पंजाब और हरियाणा को भाखड़ा जलाशय से ज्यादा पानी निकालने की सलाह दी है। निश्चित रूप से इस सलाह को उत्तर भारत क्षेत्र में पानी के प्रबंधन से जुड़ी बढ़ती मुश्किलों के प्रति एक चेतावनी के रूप में देखी जानी चाहिए। निस्संदेह, यह सलाह रोजमर्रा के परिचालन से जुड़ा मामला भी नहीं है। इसे व्यापक संदर्भों में देखें तो लगातार बढ़ती जलवायु की अनिश्चितता, खेती से जुड़े ऐसे तौर-तरीकों, जिनका दीर्घकालीन उपयोग नहीं किया जा सकता है, के बाबत यह सलाह चेताती है। निश्चित रूप से यह सलाह यह भी बताती है कि पंजाब व हरियाणा में पानी के बेहतर उपयोग को लेकर सहमति न बनने से भी इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। बांध प्रबंधन से जुड़े सूत्र बताते हैं कि भाखड़ा जलाशय का जलस्तर फिलहाल पिछले साल में इसी अवधि के दौरान के जलस्तर के मुकाबले 21 फीट अधिक है। वहीं दूसरी ओर जलाशय के अधिकतम जलस्तर तक पहुंचने में अब सिर्फ 102 फीट की जगह ही बची है। निश्चित रूप से इस दिशा में समय रहते ही अविलंब कार्रवाई करनी होगी। अन्यथा मानसून के आने के साथ वैकल्पिक उपायों की गुंजाइश भी लगातार कम होती जाती है। जलवायु परिवर्तन के गहरे होते प्रभावों के चलते हिमालयी पर्वत श्रृंखला में अधिक बर्फ के पिघलने की बढ़ती गति और बारिश के पैटर्न में लगातार आ रहे बदलाव के कारण ही जलाशय के जलस्तर में तेजी से बदलाव आने की आशंका भी बनी रहती है। यही वजह है कि इन तमाम आशंकाओं के मद्देनजर ही अविलंब नीतिगत फैसले लेने की सख्त जरूरत है।

यह विडंबना ही है कि यह चुनौती पंजाब में ऐसे समय में आ रही है, जब धान की रोपाई का मौसम चल रहा है। हालांकि, राज्य में सरकार ने पानी के बेहतर इस्तेमाल के मद्देनजर धान की खेती का कैलेंडर एक जून तक के लिये आगे बढ़ा दिया था। यह भी गौरतलब है कि आज भी पंजाब के बड़े इलाकों में खेती काफी हद तक भूजल पर ही निर्भर है। जिस सीमा तक नहरों के नेटवर्क का अधिकतम उपयोग होना चाहिए था, वह अभी भी नहीं हो पा रहा है। निस्संदेह, जब तक सतही पानी का सही तरीके से बंटवारा नहीं होता है तब तक जलाशयों में ज्यादा पानी जमा करके रखना पड़ेगा। जिसके चलते अचानक आने वाले पानी को संभालने के लिये जरूरी बाढ़ बचाव क्षमता कम हो जाती है। हमें वर्ष 2023 में पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से मिले सबक को नहीं भूलना चाहिए। तब पानी छोड़ने में कथित देरी और जलाशयों के संचालन को लेकर हुए तमाम विवादों ने राजनीतिक कड़वाहट को बढ़ाया ही था। साथ ही सरकार की बाढ़ से निबटने की तैयारियों को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हुए थे। जब बांध प्रबंधन की बात करते हैं तो इसका मकसद सिर्फ बिजली उत्पादन ही नहीं हो सकता। तब बाढ़ को नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी मकसद होना चाहिए। ऐसे वक्त में हमें जरूरी कामों की प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। सिंचाई विभाग को सुनिश्चित करना ही होगा कि नहर का पानी किसानों को समय पर मिले। खासकर उन किसानों को जिनके खेत नहर के अंतिम छोर पर स्थित हैं। इससे हमारी जमीन के ऊपर मौजूद पानी के स्रोतों पर निर्भरता ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही इन कदमों से जमीन के भीतर के पानी के भंडारों पर दबाव भी कम हो सकेगा। इसके साथ ही, सहयोगी राज्यों के साथ जलाशयों के कामकाज में पारदर्शिता और दूरदर्शिता के साथ तालमेल बैठाना होगा। पानी की भरपूर उपलब्धता से मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता बढ़नी चाहिए, न कि जोखिम को बढ़ावा दिया जाए। आज जलाशयों में जगह खाली करना भविष्य में मौसम से जुड़ी अनिश्चितताओं से निबटने के लिये सबसे अच्छा उपाय साबित हो सकता है।

फुटबाल विश्व कप में तीसरी दुनिया की दस्तक

> पिछले कुछ विश्व कप मुकाबलों में तीसरी दुनिया के देशों ने, जिसमें अफ्रीकी, एशियाई और मध्य व उत्तर अमेरिकी देश आते हैं, ने संघर्षशील फुटबाल खेल का प्रदर्शन किया है। फुटबाल की दुनिया में नासमझ समझे जाने वाले इन देशों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से यह जता दिया है कि वे भी अब फुटबाल जगत की श्रेष्ठ हस्तियों का मुकाबला कर सकते हैं।

आज से शुरू हो रहे तेईसवें विश्व कप फुटबाल में लेतिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले में तीसरी दुनिया के देश—मिस्र, दक्षिण कोरिया, ईरान, इराक, जापान, मोरक्को, घाना, अल्जीरिया, सेनेगल—कुल मिला कर 23 देश नजर आयेंगे। यह तय है कि विश्व फुटबाल पर लेतिन अमेरिकी (10 ख़िताब) और यूरोपीय देशों (12 ख़िताब) के वर्चस्व को अभी तो कोई खतरा नहीं है। पिछले कुछ विश्व कप मुकाबलों में खासकर 1982 से तीसरी दुनिया के देशों ने, जिसमें अफ्रीकी, एशियाई और मध्य व उत्तर अमेरिकी देश आते हैं, ने संघर्षशील फुटबाल खेल का प्रदर्शन किया है। फुटबाल की दुनिया में नासमझ समझे जाने वाले इन देशों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से यह जता दिया है कि वे भी अब फुटबाल जगत की श्रेष्ठ हस्तियों का मुकाबला कर सकते हैं।

आठवें दशक के अंत में जब फीफा अध्यक्ष हवेलेंज ने यह प्रस्ताव रखा था कि 1982 विश्व कप में 16 की बजाय 24 टीमें भाग लेंगी, तब उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस प्रस्ताव की आलोचना करने वालों में फुटबाल की श्रेष्ठ शक्तियां ही थीं, जबकि तीसरी दुनिया के देशों ने प्रस्ताव का स्वागत किया था। आलोचकों का कहना था कि इस स्वरूप के परिवर्तन से हालैंड की जगह न्यूजीलैंड, आयरलैंड की जगह कैमरून, उरुग्वे की जगह कुवैत, स्काटलैंड की जगह अल्जीरिया आदि कमजोर टीमें विश्व कप में पहुंच जायेंगी और इस से फुटबाल का स्तर गिरेगा, लेकिन इन्हीं आलोचकों को तब मुंह की खानी पड़ी, जब 1982 विश्व कप में अल्जीरिया ने दो बार की चैंपियन

पश्चिम जर्मनी को 2-1 से पीट दिया। अल्जीरिया ने पश्चिम जर्मनी को हराने के बाद चिली टीम को भी हराया, पर वह गोल औसत के आधार पर दूसरे चक्र में न पहुंच सके। इस विश्व कप में एक अन्य अफ्रीकी देश कैमरून ने अपने ग्रुप के तीनों ही मैच इटली, पौलेंड व पेरु के विरुद्ध बराबर रखे, वह भी मात्र गोल औसत के आधार पर प्रतियोगिता से बाहर हो गये। विश्व कप फुटबाल पर एक नजर डाली जाए तो कुछ मुकाबलों को छोड़कर तीसरी दुनिया के देशों ने कई मैचों में सराहनीय खेल का प्रदर्शन दिखाया है। पहले किसी अफ्रीकी देश के रूप में मिस्र ने 1934 में विश्व कप फुटबाल में भाग लिया था। अपने एकमात्र मैच में वे हंगरी से 4-2 से हारे। तीसरी दुनिया के देशों की विश्व कप में पहली बड़ी सफलता 1966 विश्व कप में देखने को मिली, जब उत्तरी कोरिया की टीम ने दो बार की चैंपियन इटली को 1-0 से पीट डाला। कोरिया का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा कि उन्हें सेमीफाइनल में जाने से रोकने के लिए पुर्तगाल को पूरा जोर लगाना पड़ा क्योंकि कोरिया एक समय 3-0 से आगे थी। फाइनल स्कोर 5-3 पुर्तगाल के पक्ष में रहा।

वर्ष 1970 में अफ्रीका के छोटे से देश मोरक्को ने अपनी सुंदर फुटबाल से सब का मन मोह लिया। बुलगारिया के विरुद्ध उन्होंने मैच बराबर रखा, जबकि पश्चिम जर्मनी के विरुद्ध पहले हाफ में 1-0 से बढ़त लेने के बाद 2-1 से हारे। वर्ष 1986 विश्व कप में एक बार फिर अफ्रीका के इस देश ने सबको चकित कर दिया। वह अपने ग्रुप में इंग्लैंड, पौलेंड और पुर्तगाल जैसी सशक्त टीमों से ऊपर रहे और दूसरे चक्र में खेले। पुर्तगाल को उन्होंने 3-1 से पीटा और इंग्लैंड व पौलेंड के विरुद्ध मैच गोल-रहित रखे। दूसरे चक्र में भी इस टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, पर कड़े संघर्ष के बावजूद वह पश्चिमी जर्मनी से 1-0 से हार गये। इस प्रकार मोरक्को पहली अफ्रीकी टीम बनी जो यूरोप और अमेरिका (1966 में उत्तर कोरिया के बाद) के बाहर से केवल दूसरा राष्ट्र रहा जो दूसरे दौर में पहुंचा। इसी मोरक्को ने 2022 विश्व कप फुटबाल में कमाल कर दिया जब वह चौथे स्थान पर रहा। यह किसी भी अफ्रीकी या अरब राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ विश्व कप फिनिश रहा। अपने ग्रुप में टॉप पर रहने के बाद मोरक्को ने दूसरे दौर में स्पेन को हराया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने पुर्तगाल को हराया। तीसरे स्थान के लिए वह क्रोएशिया से हार गए। कैमरून 1990 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी। उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना पर चौंकाने वाली जीत के साथ की। वे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से हारे। तीसरी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन 2002 विश्व कप फुटबाल में देखने को मिला। पहले ही दिन अफ्रीकी देश सेनेगल ने गत चैंपियन फ्रांस को 1-0 से हराया। जब सेनेगल ने अतिरिक्त समय में गोल्डन गोल के साथ स्वीडन को 2-1 से हराया, तो अंतिम आठ में पहुंचने वाली केवल दूसरी अफ्रीकी टीम बन गई (1990 में कैमरून के बाद)। एक और हैरान करने वाली टीम मेजबान दक्षिण कोरिया रही। वे पोलैंड (2-0), पुर्तगाल (1-0), इटली (2-1) और स्पेन (पेनल्टी 5-3) को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहे। ऐसा करने वाली पहली एशियाई टीम रही। तीसरे स्थान के लिए तुर्की ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया। वर्ष 2010 विश्व कप के राउंड 16 में, घाना अतिरिक्त समय के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को हराकर अंतिम आठ में पहुंचने वाला तीसरा अफ्रीकी देश बना (1990 में कैमरून और 2002 में सेनेगल के बाद)। 2014 में पहली बार, अफ्रीका (नाइजीरिया और अल्जीरिया) की दो टीमें दूसरे दौर में आगे बढ़ीं, एक उपलब्धि जो 2022 के टूर्नामेंट में दोहराई गई। पिछले विश्व कप में तीसरी दुनिया के चार देश—दो अफ्रीका से और दो एशिया से दूसरे दौर में रहे। सेनेगल, मोरक्को, जापान और दक्षिण कोरिया में से सिर्फ मोरक्को ही आगे बढ़कर चौथे स्थान पर रहा।

विश्व कप फुटबाल के मुकाबले में इस बार 23 देश तीसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 32 से 48 टीमों के स्वरूप का सबसे अधिक फायदा यूरोप को हो रहा है। साल 2022 में जब आखिरी बार 32 टीमें विश्व कप में उतरी थीं, तो यूरोप की 13 (पिछले विजेता फ्रांस सहित), लेतिन अमेरिकी की 4, मध्य व उत्तर अमेरिकी की 4, अफ्रीका की 5 और एशिया की 6 टीमों (मेजबान क़तर सहित) ने भाग लिया था। इस बार यूरोप की 16, लेतिन अमेरिकी की 6 (पिछले विजेता अर्जेंटीना सहित), मध्य व उत्तर अमेरिकी की 6 (मेजबान यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा सहित), अफ्रीका की 10, एशिया की 9 टीमें और ओशिनिया की एक टीम है। इस बार 4 देश पहली बार भाग ले रहे हैं—जॉर्डन, उज्बेकिस्तान, केप वेर्डे और कुराकाओ। कुराकाओ विश्व कप के लिए भाग करने वाला जनसंख्या (1.6 लाख) के हिसाब से सबसे छोटा देश है। मजेदार बात ये हो रही है कि विश्व कप के वार्म-अप मैचों में जहां आइवरी कोस्ट ने फ्रांस को 2-1 से और अल्जीरिया ने नीदरलैंड्स को 1-0 से हराया, जबकि इराक ने स्पेन को, घाना ने वेल्स को और कांगो ने डेनमार्क को बराबरी पर छोड़ा है। यही नहीं, तीसरी दुनिया के बहुत सारे खिलाड़ी यूरोप और अमेरिकी देशों के लिए खेल रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि उनकी पहुंच अब सर्वश्रेष्ठ टीमों में है।

प्रेरणा

गैरेज से अंतरिक्ष तक: एक वैज्ञानिक के अडिग विश्वास की कहानी

इतिहास गवाह है कि दुनिया को बदलने वाले अधिकांश लोग किसी महल या अत्याधुनिक प्रयोगशाला से नहीं, बल्कि साधारण परिस्थितियों से निकलकर आए हैं। उनके पास धन, संसाधन या सुविधाओं का अंबार नहीं था, लेकिन उनके भीतर अपने लक्ष्य को पाने की ऐसी आग थी जो हर कठिनाई को पराजित कर देती थी। भारत के महान वैज्ञानिक डॉ. यू.आर. राव का जीवन इसी सत्य का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब किसी व्यक्ति के मन में राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून और संकल्प हो, तब सीमित साधन भी असाधारण उपलब्धियों का आधार बन जाते हैं।

कर्नाटक के उडुपी जिले के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामचंद्र का बचपन किसी विशेष सुविधा या वैभव में नहीं बीता। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन शिक्षा और नैतिक मूल्यों को अत्यंत महत्व दिया जाता था। उनके माता-पिता का विश्वास था कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो जीवन की दिशा बदल सकती है। यही कारण था कि बचपन से ही रामचंद्र को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया। वे भी अध्ययन में अत्यंत रुचि लेते थे और हर नई बात को समझने की उत्सुकता रखते थे।

स्थानीय शिक्षक के पास पढ़ते हुए उनकी प्रतिभा जल्दी ही सबके सामने आ गई। शिक्षक ने देखा कि यह बालक केवल पाठ याद नहीं करता, बल्कि हर विषय को समझने का प्रयास करता है। उसकी सोच सामान्य बच्चों से अलग थी। वह प्रश्न पूछता था, तर्क करता था और हर चीज़ के पीछे छिपे कारण को जानना चाहता था। शिक्षक को विश्वास हो गया कि यह छात्र भविष्य में कोई बड़ा कार्य अवश्य करेगा। इसलिए उन्होंने उसे बेहतर शिक्षा दिलाने का निश्चय किया और बेल्लारी के एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए साथ ले गए।

विद्यालय में प्रवेश के दौरान हुई एक छोटी-सी घटना ने उनके नाम को हमेशा के लिए बदल दिया। जब उनसे नाम और परिचय पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे उडुपी के रहने वाले हैं और 'रायरु' समुदाय से संबंधित हैं। लेकिन शिक्षक ने 'रायरु' की जगह 'राव' सुन लिया और विद्यालय के अभिलेख में उनका नाम 'उडुपी रामचंद्र राव' दर्ज कर दिया गया। यही नाम आगे चलकर भारतीय विज्ञान जगत की पहचान बन गया।

जैसे-जैसे उनकी शिक्षा आगे बढ़ी, विज्ञान के प्रति उनका आकर्षण और गहरा होता गया। उन्हें आकाश, ग्रहों, तारों और ब्रह्मांड के रहस्यों में विशेष रुचि थी। वे अक्सर सोचते थे कि विज्ञान के माध्यम से मानव जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उनके लिए विज्ञान केवल किताबों तक सीमित विषय नहीं था, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास का सबसे प्रभावशाली साधन था। इसी सोच ने उनके भीतर एक बड़ा सपना जन्म दिया—भारत को वैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।

उस समय भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित देशों से काफी पीछे था। अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करना भी कई लोगों को असंभव सपना लगता था। देश के पास सीमित संसाधन थे और आधुनिक तकनीकी ढांचे का अभाव था। लेकिन कुछ दूरदर्शी वैज्ञानिकों ने यह निश्चय कर लिया था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। डॉ. यू.आर. राव उन्हीं वैज्ञानिकों में अग्रणी थे जिन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का साहस दिखाया।

जब भारतीय उपग्रह कार्यक्रम को विकसित करने का कार्य प्रारंभ हुआ, तब सुविधाओं की स्थिति बेहद साधारण थी। आज जिस अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखती है, उसकी शुरुआत किसी भव्य परिसर में नहीं हुई थी। डॉ. राव और उनकी टीम ने बेंगलुरु के पीन्या क्षेत्र में टिन की छत वाले छह छोटे गैरेज किराये पर लिए और वहीं से अपने मिशन की शुरुआत की। वहां गर्मी अत्यधिक होती थी, धूल हर समय उड़ती रहती थी और वैज्ञानिक उपकरणों को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती था।

संवेदनशील उपग्रह उपकरणों पर काम करने के लिए जिस स्तर की स्वच्छता और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, वह उन गैरेजों में उपलब्ध नहीं थी। फिर भी टीम ने हार नहीं मानी। डॉ. राव का मानना था कि यदि लक्ष्य बड़ा हो तो कठिनाइयों की शिकायत करने के बजाय उनका समाधान खोजा जाना चाहिए। वे स्वयं हर छोटी-बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहते थे। कई बार वे प्रयोगशाला की सफाई के लिए झाड़ू तक उठा लेते थे। उनके लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि महान उपलब्धियां छोटे-छोटे प्रयासों के आधार पर ही निर्मित होती हैं।

उनके सहयोगी अक्सर संसाधनों की कमी से निराश हो जाते थे। उन्हें लगता था कि विकसित देशों की तुलना में इतनी सीमित सुविधाओं के साथ विश्वस्तरीय उपलब्धि हासिल करना कठिन होगा। लेकिन डॉ. राव हमेशा उन्हें प्रेरित करते थे। उनका एक वाक्य पूरी टीम के लिए ऊर्जा का स्रोत बन गया था—"सुविधाएं विज्ञान नहीं बनातीं, संकल्प बनाता है।" यह केवल प्रेरणादायक कथन नहीं था, बल्कि उनके जीवन का मूल सिद्धांत था। उन्होंने अपने कर्मों से इसे बार-बार सिद्ध किया।

उनके नेतृत्व में भारतीय उपग्रह कार्यक्रम ने लगातार प्रगति की। उन्होंने ऐसे उपग्रहों के विकास पर जोर दिया जो सीधे देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। संचार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उपग्रह तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिक उपलब्धि बनकर नहीं रह गया, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बन गया।

डॉ. राव की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दूरदृष्टि थी। वे वर्तमान की सीमाओं में बंधकर नहीं सोचते थे। उन्हें विश्वास था कि यदि भारत अपने वैज्ञानिकों की क्षमता पर भरोसा करे तो वह विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में स्थान बना सकता है। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया, उन्हें नवाचार के लिए प्रेरित किया और आत्मविश्वास दिया कि भारतीय प्रतिभा किसी भी देश से कम नहीं है।

उनके योगदान ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई। उनके प्रयासों के कारण देश ने उपग्रह तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए। बाद के वर्षों में भारत की अनेक अंतरिक्ष उपलब्धियों की नींव उसी सोच और उसी संघर्ष पर आधारित रही, जिसे डॉ. यू.आर. राव और उनके साथियों ने कठिन परिस्थितियों में खड़ा किया था।

पूंजी बाजार में भरोसे का संकट

भारत का पूंजी बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। डीमैट खातों की संख्या लगातार बढ़ रही है, छोटे शहरों और कस्बों से नए निवेशक शेयर बाजार में आ रहे हैं और एसआइपी-म्यूचुअल फंड ने आम परिवारों को इक्विटी निवेश से जोड़ दिया है। ऐसे समय में राजेश एक्सपोर्ट्स से जुड़ा हालिया मामला केवल एक कंपनी का विवाद नहीं, बल्कि भारत में कारपोरेट गवर्नेंस, आडिट गुणवत्ता, नियामकीय सतर्कता और छोटे निवेशकों के भरोसे की गंभीर परीक्षा है। सेबी के अंतरिम आदेश में राजेश एक्सपोर्ट्स पर बड़े पैमाने पर राजस्व के गलत प्रस्तुतीकरण का आरोप लगाया गया है। वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपये के राजस्व को गलत ढंग से प्रस्तुत करने की बात कही गई है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे सामान्य लेखा-त्रुटि नहीं कहा जा सकता। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह मामला उसकी स्विस सहायक कंपनी के राजस्व को समझने और प्रस्तुत करने से जुड़े भ्रम का परिणाम है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकाला जाना चाहिए। फिर भी, यदि किसी सूचीबद्ध कंपनी के राजस्व आंकड़ों और नियामक की समझ में इतना बड़ा अंतर है तो यह पूरे बाजार ढांचे के लिए चेतावनी है।

राजेश एक्सपोर्ट्स स्वर्ण शोधन, आभूषण निर्माण और निर्यात से जुड़ी बड़ी कंपनी है। जब किसी भारतीय सूचीबद्ध कंपनी की आय का बड़ा हिस्सा विदेशी सहायक कंपनियों और सीमा-पार लेखांकन पर आधारित हो तो उसके प्रकटीकरण की जिम्मेदारी सामान्य कंपनियों से कहीं अधिक बढ़ जाती है। निवेशकों को यह जानने का अधिकार है कि राजस्व किस इकाई से आया, किन ग्राहकों से आया, नकदी में उसका रूपांतरण कैसा रहा, देय राशियां कितनी वास्तविक हैं और सहायक कंपनियों के खातों का स्वतंत्र सत्यापन किस स्तर पर हुआ। यदि किसी कंपनी में म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों, बैंकों या अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की हिस्सेदारी है तो सवाल केवल कंपनी प्रबंधन पर नहीं, बल्कि इन संस्थाओं की जांच-पड़ताल पर भी उठता है। भारत में छोटे निवेशक अक्सर मान लेते हैं कि यदि किसी कंपनी में बड़ी संस्थाओं की हिस्सेदारी है तो वह कंपनी सुरक्षित होगी, लेकिन संस्थागत निवेश हमेशा सुशासन की गारंटी नहीं होता। सत्यम घोटाले ने दिखाया कि नकदी और बैंक बैलेंस जैसे आंकड़े भी काल्पनिक हो सकते हैं। आइएलएंडएफएस संकट ने अत्यधिक कर्ज, जटिल सहायक कंपनियों और क्रेडिट रेटिंग विफलता के जोखिम को सामने रखा। यस बैंक संकट ने निजी बैंकिंग गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन की कमजोरी दिखाई। पीएनबी-नीरव मोदी प्रकरण ने बैंकिंग व्यवस्था और लेटर आफ अंडरटेकिंग के दुरुपयोग को उजागर किया था।

राजेश एक्सपोर्ट्स जैसा मामला यह संकेत देता है कि सूचीबद्ध कंपनियों में भी सीमा-पार लेनदेन और सहायक कंपनियों के लेखांकन पर निगरानी बढ़ानी होगी। भारत को अब घोटाले के बाद सुधार करने की संस्कृति से आगे बढ़कर जोखिम की पहले पहचान और रोकथाम की प्रणाली बनानी होगी। राजेश एक्सपोर्ट्स मामले में आडिट व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न उठते हैं। यदि कोई कंपनी लगातार विशाल राजस्व दिखा रही थी तो आडिटर ने ग्राहक पुष्टि, बैंक ट्रेल, सहायक कंपनी आडिट रिपोर्ट, स्टाक रिकार्ड, देय राशियों और आपसी कंपनी लेनदेन की जांच किस गहराई से की? बोर्ड की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नियामकीय दृष्टि से सेबी की कार्रवाई महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि कथित गलत प्रस्तुतीकरण कई वर्षों से चल रहा था तो शुरुआती चेतावनी संकेत पहले क्यों नहीं पकड़े गए? स्टाक एक्सचेंज, आडिटर, विश्लेषक, रेटिंग एजेंसियां, ऋणदाता और संस्थागत निवेशक क्या देख रहे थे? एआइ और डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से असामान्य अनुपात, देय राशियों की अचानक वृद्धि, नकदी प्रवाह का अंतर और बाजार पूंजीकरण बनाम राजस्व के असामान्य अंतर को स्वतः चिह्नित किया जा सकता है। छोटे निवेशकों के लिए भी यह घटना बड़ा सबक है। निवेश करते समय केवल शेयर मूल्य, राजस्व और ब्रांड पर ध्यान न दें। बड़ा टर्नओवर हमेशा मजबूत कंपनी का प्रमाण नहीं होता। यदि राजस्व बहुत बड़ा है, लेकिन लाभ कम है, नकदी प्रवाह कमजोर है और देय राशियां बढ़ रही हैं तो सावधानी जरूरी है। सस्ता या आकर्षक शेयर हमेशा मूल्यवान नहीं होता, कई बार वह गवर्नेंस जोखिम का संकेत होता है।

भारत को अब एकीकृत कारपोरेट जोखिम डैशबोर्ड बनाना चाहिए, जिसमें सेबी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, रिजर्व बैंक, जीएसटी नेटवर्क, सीमा शुल्क, स्टाक एक्सचेंज और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के डाटा को जोखिम-आधारित ढंग से जोड़ा जाए। राजेश एक्सपोर्ट्स मामला दर्शाता है कि पूंजी बाजार में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, बल्कि भरोसा है। बैलेंस शीट में संपत्तियां दिखाई जा सकती हैं, राजस्व बताया जा सकता है, मूल्यांकन बनाया जा सकता है, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाए तो उसकी दोबारा बहाली मुश्किल है। मजबूत आडिट, पारदर्शी प्रकटीकरण, सशक्त बोर्ड, डाटा-आधारित निगरानी और जागरूक निवेशक-यही भविष्य के भारतीय पूंजी बाजार की सुरक्षा के पांच स्तंभ हैं।

अभियान

जब एक फकीर ने राजा का अभिमान तोड़ा: आत्मज्ञान की अमूल्य कीमत

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जो केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहनतम सत्यों को सरल ढंग से समझाने का माध्यम भी हैं। उपनिषदों की कथाएं विशेष रूप से मानव जीवन, आत्मा, ज्ञान, अहंकार और मोक्ष जैसे विषयों पर गहरा प्रकाश डालती हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा छांदोग्य उपनिषद में वर्णित राजा जनश्रुति और महान ज्ञानी रायक्वा की है। यह कथा केवल एक राजा और एक ऋषि की मुलाकात की कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, ज्ञान की वास्तविक प्रकृति और सच्ची विनम्रता का गहन दर्शन प्रस्तुत करती है।

बहुत प्राचीन समय की बात है। जनश्रुति नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर उसकी उदारता तथा दानशीलता की चर्चा होती थी। उसने अनेक धर्मशालाएं बनवाई थीं, यात्रियों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था की थी तथा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए अपने खजाने के द्वार खोल रखे थे। उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। लोग उसे दानवीर, धर्मात्मा और महान राजा कहकर सम्मान देते थे।

समय के साथ यह सम्मान धीरे-धीरे उसके मन में एक सूक्ष्म अहंकार का रूप लेने लगा। उसे लगने लगा कि संसार में उससे अधिक पुण्यात्मा और उदार व्यक्ति कोई नहीं है। वह स्वयं को प्रजा का सबसे बड़ा हितैषी और धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक मानने लगा था। यद्यपि उसके कार्य अच्छे थे, लेकिन उनके पीछे कहीं न कहीं प्रशंसा और यश पाने की इच्छा भी जुड़ गई थी। यही वह बिंदु था जहां से उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की भूमिका तैयार हो रही थी।

एक रात राजा अपने महल की ऊंची छत पर विश्राम कर रहा था। वातावरण शांत था और आकाश तारों से भरा हुआ था। तभी उसकी दृष्टि आकाश में उड़ते हुए दो हंसों पर पड़ी। वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। राजा ने उत्सुकतावश उनकी बातें सुननी शुरू कर दीं। एक हंस ने दूसरे से कहा, "सावधान रहना। क्या तुम राजा जनश्रुति के पुण्य और यश का प्रकाश नहीं देख रहे? उसकी कीर्ति इतनी तेजस्वी है कि कहीं तुम उसके तेज में जल न जाओ। आज संसार में उससे बड़ा दानी और धर्मात्मा कौन है?"

दूसरा हंस हल्का-सा हंसा और बोला, "तुम ऐसा कह रहे हो मानो जनश्रुति रायक्वा से भी बड़ा हो। राजा की प्रसिद्धि केवल बाहरी है। वह अभी भी यश और प्रशंसा का इच्छुक है। लेकिन रायक्वा का ज्ञान उससे कहीं ऊंचा है।" पहला हंस आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, "यह रायक्वा कौन है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस महान राजा से भी श्रेष्ठ माना जाता है?" दूसरे हंस ने उत्तर दिया, "जिस प्रकार जुए में जीतने वाला खिलाड़ी सभी अंक अपने पक्ष में कर लेता है, उसी प्रकार रायक्वा ऐसा ज्ञानी है जिसके भीतर समस्त पुण्य और ज्ञान का सार समाहित है। उसके सामने राजा की प्रसिद्धि और दान का कोई महत्व नहीं।"

इतना कहकर दोनों हंस आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी बातचीत राजा के हृदय में गहराई तक उतर गई। पहली बार उसे यह अनुभव हुआ कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे उससे अधिक महान माना जाता है। यह विचार उसे बेचैन करने लगा। पूरी रात वह सो नहीं सका। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न घूमता रहा—आखिर यह रायक्वा कौन है?

अगली सुबह उसने अपने विश्वस्त सेवकों को आदेश दिया कि वे उस व्यक्ति की खोज करें। राजा की आज्ञा पाकर सेवक विभिन्न दिशाओं में निकल पड़े। उन्होंने नगरों, गांवों और आश्रमों में खोजबीन की, लेकिन रायक्वा का कोई पता नहीं चला। काफी समय बाद एक सेवक ने एक अत्यंत साधारण दृश्य देखा। एक पुराने रथ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ था और अपने शरीर को खुजला रहा था। उसके वस्त्र साधारण थे, रहने का कोई विशेष स्थान नहीं था और उसे देखकर कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह कोई महान ज्ञानी होगा।

सेवक ने उसके पास जाकर पूछा, "क्या आप रायक्वा हैं?" उस व्यक्ति ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, "हाँ, मैं ही रायक्वा हूं।"

सेवक तुरंत महल लौटा और राजा को यह समाचार सुनाया। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसकी चर्चा आकाश में उड़ते हंस कर रहे थे, वह इतना साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति हो सकता है। फिर भी वह स्वयं उससे मिलने का निश्चय करके चल पड़ा।

राजा अपने साथ छह सौ गायें, सोने की एक बहुमूल्य माला और खच्चरों द्वारा खींचा जाने वाला एक सुंदर रथ लेकर रायक्वा के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से सारी भेंटें उनके चरणों में रख दीं और कहा, "हे महात्मा, कृपया इन उपहारों को स्वीकार कीजिए और मुझे वह ज्ञान प्रदान कीजिए जिसने आपको महान बनाया है।" रायक्वा ने राजा की ओर देखा और शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, "इन गायों, इस रथ और इस सोने को वापस ले जाओ। आत्मज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे धन देकर खरीदा जा सके।"

राजा स्तब्ध रह गया। जीवन में पहली बार किसी ने उसके दान को अस्वीकार किया था। वह निराश होकर लौट आया, लेकिन उसके मन में ज्ञान पाने की इच्छा और भी प्रबल हो गई।

कुछ समय बाद वह फिर लौटा। इस बार वह एक हजार गायें, अधिक सोना, एक उत्कृष्ट रथ और अपनी पुत्री को भी साथ लाया। उसने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा, "हे महात्मा, मैं धन के कारण नहीं आया हूं। मैं सत्य की खोज में आया हूं। कृपया मुझे जीवन का वास्तविक ज्ञान प्रदान करें।"

रायक्वा ने देखा कि राजा का अहंकार पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर अब जिज्ञासा थी, विनम्रता थी और सत्य को जानने की तीव्र आकांक्षा थी। उन्होंने समझ लिया कि यह व्यक्ति अब ज्ञान ग्रहण करने के योग्य हो चुका है। रायक्वा ने राजा को समझाना शुरू किया कि संसार में लोग अनेक शक्तियों की पूजा करते हैं। कोई अग्नि को सर्वोच्च मानता है, कोई वायु को, कोई सूर्य को और कोई अन्य देवताओं को। ये सभी शक्तियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन सबके पीछे एक और गहरा सत्य विद्यमान है। वह सत्य है आत्मा का।

उन्होंने कहा, "वायु सब कुछ अपने साथ बहा सकती है, अग्नि सब कुछ जला सकती है, प्राण समस्त जीवों को जीवन प्रदान करता है, लेकिन इन सभी के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है, वह आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। उसे कोई बना नहीं सकता और न कोई नष्ट कर सकता है। वही समस्त अस्तित्व का आधार है।"

राजा ध्यानपूर्वक सुनता रहा। रायक्वा आगे बोले, "हे राजन, दान करना अच्छा है, लेकिन दान के साथ यदि अहंकार जुड़ जाए तो उसका आध्यात्मिक मूल्य समाप्त हो जाता है। दान इसलिए मत करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। दान इसलिए भी मत करो कि तुम्हें उससे पुण्य प्राप्त होगा। दान इसलिए करो क्योंकि तुम समझते हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है, वह वास्तव में तुम्हारा नहीं है। वह ईश्वर और आत्मा का दिया हुआ है, जिसे दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग में लाना तुम्हारा कर्तव्य है।" यह शिक्षा राजा के हृदय को छू गई। उसे पहली बार समझ में आया कि वह अब तक दान तो कर रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं अपने पुण्य और यश का अभिमान भी छिपा हुआ था। उसने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और विनम्रता से प्राप्त होता है। रायक्वा ने उसे यह भी बताया कि जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को जान लेता है, वह संसार की वस्तुओं का दास नहीं रहता। वह उनका उपयोग करता है, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होता। उसके भीतर संतोष उत्पन्न हो जाता है और फिर उसे किसी बाहरी प्रशंसा या सम्मान की आवश्यकता नहीं रहती।

राजा जनश्रुति का जीवन इस ज्ञान से पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले की तरह दान तो करता था, लेकिन उसके पीछे यश पाने की इच्छा नहीं थी। वह अधिक विनम्र, अधिक करुणामय और अधिक आत्मचिंतनशील बन गया। उसने समझ लिया कि धन का मूल्य तभी है जब उसका उपयोग निस्वार्थ भाव से किया जाए।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

सुशासन के 12 वर्ष और विकसित भारत की ओर लंबी छलांग : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के सड़क मार्ग बने आधुनिक

▸▸ भारतमाला परियोजना से गुजरात को मिली नई गति : 1068 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क से गुजरात फास्ट लेन पर

▸▸ हाल ही में प्रधानमंत्री के करकमलों से वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 एवं 7 का लोकार्पण किया गया

▸▸ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा तथा राजकोट जैसे औद्योगिक महानगरों के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी

▸▸ गुजरात में लॉजिस्टिक्स अधिक कार्यक्षम बना, मार्केट तथा फैक्ट्रियों के बीच एक्सेस में सुधार होने से उद्योगों को लाभ

▸▸ राज्य के बंदरगाहों तक सुदृढ़ कनेक्टिविटी, रोजगार में वृद्धि एवं माल-सामान की तेज आवाजाही संभव बनी

गांधीनगर, 11 जून : इस वर्ष श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 26 मई, 2014 को उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात ने देश के 'ग्रोथ इंजन' के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत बनाया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य के सड़क मार्गों को आधुनिक बनाने का अभियान शुरू किया था; जिससे राज्य में परिवहन अधिक सुगम बने, औद्योगिक विकास तेज हो और विकास का लाभ सुदूरवर्ती व्यक्ति तक पहुँचे। इसी प्रकार समग्र देश में मजबूत रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए उनके दिशा-निर्देशन में वर्ष 2017 में भारतमाला परियोजना शुरू की गई थी।

भारतमाला परियोजना समग्र देश में राजमार्गों के विकास की एक महत्वपूर्ण परियोजना है; जिससे सड़कों पर कार्गो की आवाजाही में सुधार हो, लॉजिस्टिक्स लागत कम हो तथा आर्थिक कॉरिडोर, सीमावर्ती सड़कों, समुद्र तटीय सड़कों और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क से देशभर में कनेक्टिविटी में वृद्धि हो। इस परियोजना अंतर्गत समग्र देश में 50 आर्थिक कॉरिडोरों का निर्माण करने, 550 जिलों को राष्ट्रीय राजमार्ग के लिंकेज से कनेक्टिविटी देने तथा सड़क यात्रा के औसत समय में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात में इस परियोजना अंतर्गत लगभग 1068 किलोमीटर के आधुनिक सड़क मार्गों के नेटवर्क से गुजरात के विकास को नई दिशा मिली है।

इस परियोजना अंतर्गत देश के उत्तरी क्षेत्र के राज्यों-प्रदेशों की पूर्वी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी उद्देश्य है। साथ ही; जामनगर, कंडला तथा मुंद्रा जैसे बंदरगाहों से उत्तरी क्षेत्र के राज्यों-प्रदेशों को विभिन्न उत्पादों के आयात-निर्यात की वैश्विक सुविधा उपलब्ध कराने की भी इस परियोजना की मंशा है।

गुजरात के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना

जब भारत सरकार ने वर्ष 2017 में भारतमाला परियोजना शुरू की, तब गुजरात की समग्र कार्यक्रम में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में से एक के रूप में पहचान की गई। 1600 किलोमीटर से अधिक का समुद्र तट, महत्वपूर्ण औद्योगिक कॉरिडोर एवं मुंद्रा, कंडला तथा हजीरा जैसे बंदरगाहों के साथ गुजरात को ऐसे हाईवे नेटवर्क की आवश्यकता थी, जो राज्य की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो। भारतमाला अंतर्गत विकसित सड़क नेटवर्क ने इन बंदरगाहों को राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के साथ अधिक तेज और कार्यक्षम रूप से जोड़ा है। आज गुजरात में इस परियोजना के प्रथम चरण में 65,000 करोड़ रुपए के खर्च से 1557 किलोमीटर के 45 प्रोजेक्ट मंजूरी किए गए हैं, जिनमें से 1068 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है। अत्याधुनिक ढाँचागत सुविधाएँ विकासित करने और इन्फ्रास्ट्रक्चर को तेजी से पूर्ण करने में गुजरात अग्रसर रहा है।

इस परियोजना अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो राजस्थान के साँचौर से गुजरात के पाटण जिले के सांतलपुर तक लगभग 125 किलोमीटर लंबाई का सड़क मार्ग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (6 लेन) के रूप में निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त; अमृतसर-जामनगर के बीच लगभग 1256 किलोमीटर के आर्थिक कॉरिडोर का भी निर्माण होने वाला है। अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे तथा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे भी इस परियोजना के महत्वपूर्ण मार्ग हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रहे हैं।

भारतमाला परियोजना की सफलता

माल की तेज आवाजाही : भारत के सबसे व्यस्त फ्रेट कॉरिडोरों की सूची में गुजरात शामिल है। भारतमाला अंतर्गत अपग्रेड किए गए हाईवे के कारण अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आई है। तेज एवं यातायात-मुक्त परिवहन के साथ लॉजिस्टिक्स खर्च में भी कमी आई है।

बंदरगाहों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी : भारतमाला परियोजना अंतर्गत समुद्र तट तथा बंदरगाहों को जोड़ने वाले सड़क मार्गों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके कारण हाईवे और बंदरगाहों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत बनी है।

रोजगार तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था : राजमार्ग निर्माण से इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न वर्गों के लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। स्थानीय व्यवसाय को भी इससे गति मिली है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में तेज भूमि अधिग्रहण, समय पर मंजूरियाँ तथा इस परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ निकटता से कार्य करती है। इसके कारण गुजरात में इस परियोजना अंतर्गत सफलतापूर्वक कार्य पूरे किए गए हैं। भारत जब वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, तब भारतमाला परियोजना उस विकास लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार देती है।

सूरत स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

सूरत स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत प्लेटफॉर्म क्रमांक 2, 3 एवं 4 के बीच थ्रू रूफ लॉन्चिंग के कार्य के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

शॉर्ट टर्मिनेट / शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें:-

17 जून, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12935 बांद्रा टर्मिनस–सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस उधना स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। अतः यह ट्रेन उधना एवं सूरत स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

14 जून, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 20925 सूरत–अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस उधना स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। अतः यह ट्रेन सूरत एवं उधना स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

15 जून, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 20926 अमरावती–सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस उधना स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। अतः यह ट्रेन उधना एवं सूरत स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

नीति आयोग की बैठक में तय हुआ 'विकसित भारत' का एजेंडा

नई दिल्लीः पीएम मोदी ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करते हुए 'विकसित भारत@2047' को देश के हर राज्य, ज़िले, ब्लॉक और गांव का सामूहिक संकल्प बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की 70 करोड़ युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है और राज्यों को इस 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' को 'डेवलपमेंट डिविडेंड' में बदलने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने MSME और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और मुक्त व्यापार समझौतों के तहत विदेशी निवेश आकर्षित करने पर भी जोर दिया। नीति आयोग की बैठक में PM मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को भविष्य के अवसर के रूप में देखते हुए युवाओं को नई तकनीकों के अनुरूप कौशल विकसित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। इसके अलावा अल-नीनो के संभावित प्रभावों को देखते हुए जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया गया।

केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन डॉ. जितेंद्र सिंह ने उद्योग जगत से भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया

अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद 400 से अधिक स्टार्ट-अप के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम का विस्तार हुआः डॉ. जितेंद्र सिंह डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, वेंचर कैपिटल और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे डॉ. जितेंद्र सिंह ने अनुसंधान एवं विकास में अधिक परोपकार की वकालत की, कहा कि विज्ञान में निवेश मानवता की सेवा है

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान; केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज उद्योग जगत के दिग्गजों से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश और भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया यह है।

10वें इन-स्पेस इंडस्ट्री कनेक्ट को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने रेखांकित किया कि भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम ने जबरदस्त नवाचार और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया है, लेकिन वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में नेतृत्व हासिल करने के लिए स्थापित उद्योगों द्वारा अधिक धन, उत्पादन शक्ति और बाजार पहुंच के साथ एक मजबूत साझेदारी की आवश्यकता होगी।

डॉक्टर। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना रणनीतिक क्षेत्रों के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक ऐतिहासिक बदलाव है। उन्होंने इन सुधारों को एक साहसिक निर्णय बताया, जिसने भारत की उद्यमशीलता की अंतर्निहित क्षमता को खोल दिया और कम समय में देश के अंतरिक्ष इकोसिस्टम को पुनर्जीवित किया।

इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए की गई नीतिगत पहलों पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का पालन भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 द्वारा किया गया, जिसने हितधारकों को रणनीतिक दिशा और नियामक स्पष्टता प्रदान की। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रणाली के उदारीकरण ने निवेश आकर्षित करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारत के एकीकरण में सुधार करने में मदद की है। मंत्री महोदय ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) की स्थापना को एक प्रमुख संस्थागत सुधार बताया, जिसने अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में गैर-सरकारी भागीदारी को सक्षम, प्रोत्साहित, अधिकृत और पर्यवेक्षित किया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रणालियों के माध्यम से नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में नवाचार और व्यावसायीकरण की सुविधा के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपये का टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि सीड फंडिंग, इनक्यूबेशन सपोर्ट, कौशल विकास कार्यक्रम और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम से संबंधित पहल देश की विस्तारित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य के लिए तैयार प्रतिभाओं को तैयार करने में योगदान दे रही हैं।

भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के तेजी से विकास का उल्लेख करते हुए, मंत्री ने कहा कि जो कुछ अग्रणी उद्यमों के साथ शुरू हुआ था, वह आज एक ऐसे इकोसिस्टम में विकसित हो गया है जिसमें 400 से अधिक स्टार्ट-अप और सैकड़ों बड़ी और छोटी कंपनियां शामिल हैं। स्काईरूट एयरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस, पिक्सल, गैलेक्सी, दिगंतारा और ध्रुव स्पेस जैसी कंपनियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वे भारत की उद्यमशीलता क्षमताओं और तकनीकी नवाचार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान में परोपकार की एक मजबूत संस्कृति बनाने का आह्वान करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि परोपकार पारंपरिक रूप से धर्मार्थ कार्यों की ओर निर्देशित किया गया है, लेकिन अनुसंधान और नवाचार में निवेश को समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा के रूप में भी मान्यता दी जानी चाहिए।

मंत्री ने उद्योग के हितधारकों से इस विकसित हो रहे अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में काम करते समय आने वाली चुनौतियों और सीमाओं के बारे में खुले रहने की भी अपील की। उन्हें सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए, उन्होंने नीति निर्माताओं और उद्योग के बीच एक खुला और रचनात्मक संवाद बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने तेजी से अनुमोदन, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और प्रभावी एकल-खिड़की तंत्र की आवश्यकता पर उद्योग की चिंताओं को स्वीकार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासन का उद्देश्य अप्रत्याशित बाधाएं पैदा करने के बजाय नवाचार को प्रोत्साहित करना होना चाहिए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आत्मनिर्भर अंतरिक्ष के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों, निवेशकों और राज्य सरकारों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप की तत्परता को स्थापित उद्योगों के पैमाने, वित्तीय ताकत और निष्पादन क्षमताओं द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में प्रचुर प्रतिभा और उद्यमशीलता की ऊर्जा है, और लंबे समय से जिस चीज की कमी थी, वह सिर्फ एक अनुकूल नीतिगत माहौल था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए सुधारों ने उस इकोसिस्टम का निर्माण किया है और नवाचार और उद्यम के लिए नए रास्ते खोले हैं।

अपने समापन में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की आकांक्षाओं को केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सभी हितधारकों से भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।

सौर ऊर्जा ने बदला जीवन : पीएम-कुसुम से बदल रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था

▸▸ नर्मदा, डांग तथा तापी के सुदूरवर्ती गाँवों में अब खेती केवल वर्षा आधारित नहीं, सौर ऊर्जा यहाँ के किसानों के लिए आशा की किरण बनकर आई है

▸▸ पीएम-कुसुम अंतर्गत गुजरात में 695 मेगावाट क्षमता के 256 सोलर पावरप्लांट कार्यरत, लगभग 2.97 लाख खेतीबाड़ी पंपों का सोलराइजेशन

▸▸ पीएम-कुसुम योजना किसानों को ऊर्जा एवं जल सुरक्षा प्रदान करने के अलावा डीजल उपयोग घटाकर पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है : श्री ऋषिकेश पटेल, ऊर्जा मंत्री, गुजरात

गांधीनगर : एक समय था, जब डांग के उमरगाडा गाँव के किसान रामूभाई वाघमारे के लिए वर्षा ही जीवन का आधार था। वर्षा ऋतु अच्छी रहे, तो फसल होती, अन्यथा पूरा वर्ष मुश्किलों में बीतता। सिंचाई के लिए रात में खेतों में जाना पड़ता, बिजली की अनिश्चितता तथा पानी की कमी एक कड़वी वास्तविकता थे।

आज स्थिति बदल गई है। उनके खेत में स्थापित सोलर वॉटर पंप सूर्योदय से सूर्यास्त तक निरंतर पानी देता है। अब सिंचाई के लिए रात-रातभर जागना नहीं पड़ता। अब साल में एक से अधिक बार फसल उगाई जा सकती है।

इस परिवर्तन के पीछे है केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना, जो गुजरात के आदिजाति क्षेत्रों में विकास का नया अध्याय लिख रही है।

राज्य में हाल में 21 हजार से अधिक सोलर वॉटर पंप कार्यरत हैं। नर्मदा, डांग तथा तापी जैसे जिलों में हजारों किसान अब डीजल खर्च, बिजली की अनिश्चितता तथा वर्षा की सीमाओं से मुक्त बन रहे हैं।

तापी के गवाण गाँव के गावजीभाई वसावा कहते हैं कि पहले खेती केवल वर्षा ऋतु तक सीमित थी। आज सोलर पंप की सहायता से वर्ष के दौरान किसान एक से अधिक फसल उगा सकते हैं। यहाँ धरतीपुत्र खेत में घास-चारा उगाकर पशुपालन के माध्यम से अतिरिक्त आय भी अर्जित करते हैं।

नर्मदा जिले के जूना मोसदा गाँव के ईश्वरभाई वसावा के लिए तो यह योजना जीवन बदलने वाली सिद्ध हुई है। एक समय ऐसा था, जब खेती से पर्याप्त आय न मिलने के कारण रोजगार के लिए शहरों में मजदूरी करने जाना पड़ता था, परंतु अब वे वर्ष में तीन फसल उगा सकते हैं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है।

इस योजना की सफलता केवल किसानों के अनुभवों से ही नहीं, बल्कि योजना की की व्यापकता में भी दिखता है।

पीएम-कुसुम के घटक-सी अंतर्गत गुजरात में 695 मेगावाट क्षमता के 256 सोलर पावर प्लांट कार्यरत हुए हैं, जिसके कारण अनुमानित 2.97 लाख खेतीबाड़ी पंपों का सोलराइजेशन हुआ है। राजकोट जिला 81 मेगावाट क्षमता के साथ राज्य में अग्रसर है।

ऊर्जा मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल के अनुसार यह योजना किसानों को ऊर्जा एवं पानी की सुरक्षा प्रदान करने के अलावा डीजल का उपयोग घटाकर पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

ऊर्जा मंत्री योजना का विवरण देते हुए कहते हैं, "इस योजना अंतर्गत तीन घटक ए, बी व सी लागू किए गए हैं। घटक-ए अंतर्गत 163 मेगावाट के पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) किए गए हैं, जिसका कार्य हाल में प्रगत्याधीन है, जबकि घटक-बी अंतर्गत जहाँ ग्रिड सप्लाई उपलब्ध न हो या टेक्नो-कॉमर्शियस दृष्टि से वायेबल न हो; ऐसे दूर-सुदूरस्थ क्षेत्रों, दूरदराजी प्रदेशों और वन-जंगल क्षेत्रों में सिंचाई के लिए / मौजूदा डीजल पंप सेट को हटाकर सोलर एग्रीकल्चर पंप स्थापित किए जाते हैं। योजनानुसार लाभार्थी को कुल सिस्टम खर्च की 30 प्रतिशत केन्द्र सरकार की सहायता (सीएफए) तथा 30 प्रतिशत राज्य सरकार की सब्सिडी मिलती है, जबकि शेष 40 प्रतिशत और अदेय सब्सिडी की राशि लाभार्थी किसान को देनी होती है। यह सहायता 7.5 होर्स पावर (एचपी) तक की क्षमता के पंप सेट के लिए ही है।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जंगल क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष उदारता दिखाते हुए अतिरिक्त सब्सिडी का विशेष प्रावधान किया है, जिसके अनुसार आदिजाति एवं वन क्षेत्र के किसानों केन्द्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत तथा राज्य सरकार की ओर से 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इसके चलते किसानों को एक रुपए का भी योगदान नहीं देना पड़ता है, जबकि गैरआदिजाति क्षेत्र एवं वन क्षेत्र के किसानों को केन्द्र की ओर से 30 व राज्य की ओर से 70 प्रतिशत सब्सिडी के साथ केवल न्यूनतम निर्धारित शुल्क ही देना होता है। इस घटक अंतर्गत अब तक 22,787 सोलर पंप कार्यरत किए गए हैं। गुजरात के आदिजाति क्षेत्रों में आज सोलर पंप केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि किसान के जीवन में विश्वास का प्रतीक है। ये पंप अधिक फसल, अधिक आय और अधिक अच्छी जीवनशैली का साधन हैं।

हार के बाद भी सरकारी बंगलों के प्रति आकर्षण राजनेताओं के कथनों और कार्यों में विरोधाभास

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारतीय राजनीति का प्रभाव ऐसा है कि नेता जनता को सलाह देते फिरते हैं, लेकिन जब नियमों का पालन करने की बात आती है, तो वे दूसरों के साथ चालबाजी करते नजर आते हैं। हमारे लोकतंत्र में नेताओं के कथन और कार्य अलग-अलग होते हैं। नेताओं का अंतर्निहित संदेश यह है कि हमें उनके कथनों का पालन करना चाहिए, न कि उनके कार्यों का।

क्योंकि लोकतंत्र में, शासकों को मिलने वाली अधिकतम सुविधाओं के कारण, वे (नेता) राजशाही जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। पाला बदलने के कई कारणों में से एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकारी सुविधाएं मिलती रहती हैं। कुछ लोग बंगलों से आकर्षित होते हैं। कुछ लोग सुरक्षा के लिए लगातार आने-जाने से आकर्षित होते हैं। जब उन्हें सत्ता के साथ सरकारी बंगला मिल जाता है, तो लोग अपना पसंदीदा रंग, बाथरूम के सामान, बंगले के पर्दे, सीलिंग फैन आदि बदल देते हैं।

कुछ लोग तो अपने लिए बड़े-बड़े बंगले भी बनवा लेते हैं और उन्हें ऐसे सजाते हैं जैसे उन्हें स्थायी निवास मिल गया हो। मुफ्त में मिली चीज़ को कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि भारत की इस अनिश्चित राजनीति में कौन कब बाहर हो जाएगा, पर कुछ प्रभावशाली और कुशल राजनेता जानते हैं कि समय कभी भी बदल सकता है। इसी बात को समझते हुए वे भ्रष्टाचार के ज़रिए अपने लिए अलग से फार्महाउस बनवा लेते हैं, ताकि जब सरकारी बंगला खाली करने का समय आए तो कोई समस्या न हो।

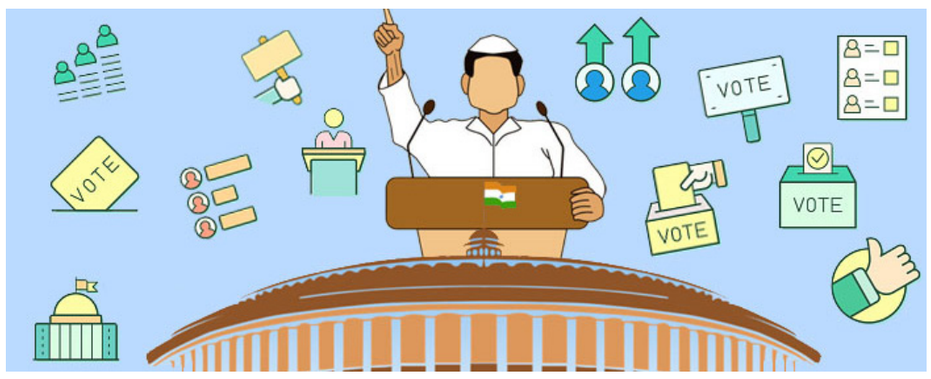

अब जब भारतीय राजनेता पाँच साल तक शासन करने के बाद हार जाते हैं, तो वे सरकार द्वारा दिए गए बंगलों जैसी सुविधाओं को अपना समझने लगते हैं। कमजोर कानून की खामियों और सत्ताधारी दल के साथ मिलीभगत के कारण ये लोग सरकारी बंगलों को खाली करने से कतराते हैं। वहाँ न तो बुलडोजर चलते हैं और न ही कोई तोड़फोड़ होती है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों में नैतिक साहस की कमी है, इसलिए बुलडोजर केवल गरीबों पर ही चलते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद ⇌ पटना के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढाए जाएंगे

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	चलाने के दिन	से विस्तृत
09447	अहमदाबाद – पटना	बुधवार	17.06.2026
09448	पटना - अहमदाबाद	शुक्रवार	19.06.2026

ठहराव के समय और ट्रेन की बनावट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं।

ट्रेन नंबर 09447 के बढ़ाए गए फेरों के लिए बुकिंग 12.06.2026 से सभी PRS काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। यह ट्रेन स्पेशल किराए वाली स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाईक और फोलो करें
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें

पारिवारिक विवाद का खौफनाक अंत: बहू और उसकी मां की हत्या के बाद बुजुर्ग ने की आत्महत्या की कोशिश, भरूच में सनसनी

भरूच। गुजरात के भरूच जिले से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पारिवारिक विवाद और रिश्तों में बढ़ते तनाव ने एक परिवार को ऐसी त्रासदी में धकेल दिया, जिसमें दो महिलाओं की जान चली गई, जबकि आरोपी बुजुर्ग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। इस दोहरे हत्याकांड ने न केवल स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है, बल्कि एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि घरेलू विवाद जब संवाद और समझदारी की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं, तो उनके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं।

पुलिस के अनुसार भरूच शहर के व्होरावाड़ और कोठी क्षेत्र में रहने वाले जैनुल अब्बास जनोरवाला पर अपनी बहू अलीफिया यूसुफ जनोरवाला और उसकी मां शाहनाज नमकवाला की हत्या करने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने धारदार हथियार से दोनों महिलाओं पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने स्वयं पर भी चाकू से कई वार किए और आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

घटना का खुलासा उस समय हुआ जब पुलिस को दो अलग-अलग स्थानों पर संदिग्ध परिस्थितियों में दो महिलाओं के शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों मृतक महिलाओं के बीच मां-बेटी का संबंध था और दोनों की हत्या एक ही घटनाक्रम का हिस्सा प्रतीत होती है।

भरूच के डिप्टी एसपी एम.एम. गांगुली ने बताया कि मामले की जांच कई स्तरों पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन हत्या के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं और परिजनों सहित अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के अनुसार मृतका अलीफिया के पति डॉ. यूसुफ जनोरवाला पेशे से बीएचएमएस चिकित्सक हैं। वे भरूच के कोठी क्षेत्र में बुरहानी नाम से एक क्लिनिक संचालित करते हैं। परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां भी थीं। स्थानीय लोगों के अनुसार परिवार में पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। हालांकि विवाद की प्रकृति क्या थी और वह किस स्तर तक पहुंच चुका था, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई है कि परिवार के सदस्यों के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। बताया जा रहा है कि इन्हीं मतभेदों ने धीरे-धीरे गंभीर रूप ले लिया। हालांकि जांच एजेंसियां अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही हैं और सभी तथ्यों को एकत्र करने के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रही हैं।

घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक पारिवारिक विवाद इतना भयावह रूप ले सकता है। कई लोगों ने मृतक महिलाओं को शांत स्वभाव का बताया और घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। फोरेंसिक विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों ने दोनों घटनास्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया है। हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटनाक्रम किस क्रम में घटित हुआ और आरोपी ने दोनों महिलाओं तक पहुंचकर वारदात को कैसे अंजाम दिया। इसके अलावा मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, पारिवारिक संबंधों और हाल के घटनाक्रमों की भी जांच की जा रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। चूंकि आरोपी अस्पताल में भर्ती है, इसलिए उसके स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जांच अधिकारियों का मानना है कि उसके बयान से पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि परिवारों में उत्पन्न होने वाले विवादों का समय रहते समाधान न होने पर परिस्थितियां कभी-कभी अत्यंत गंभीर रूप ले सकती हैं। संवादहीनता, मानसिक तनाव, आपसी अविश्वास और लंबे समय तक चले मतभेद रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। ऐसे मामलों में परिवार और समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ताकि तनाव बढ़ने से पहले समाधान का रास्ता निकाला जा सके।

फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के समय, हमले की प्रकृति और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अधिक जानकारी सामने आ सकेगी। जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगा रही हैं कि क्या घटना पूरी तरह पूर्व नियोजित थी या किसी अचानक हुए विवाद का परिणाम।

भरूच में हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। दो महिलाओं की मौत और एक बुजुर्ग द्वारा आत्महत्या की कोशिश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच की जाएगी तथा सभी तथ्यों को सामने लाने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे शहर की नजरें जांच के नतीजों और अस्पताल में भर्ती आरोपी की स्थिति पर टिकी हुई हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईआईटी गांधीनगर में डीएसटी द्वारा वित्त पोषित सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी और 3 रिसर्च क्लस्टर का शुभारंभ किया

▸▸ उद्योग साझेदारी, भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा और अनुवाद संबंधी अनुसंधान भारत की नवाचार यात्रा को आकार देंगे: डॉ. जितेंद्र सिंह

▸▸ लगभग 70 उद्योग संस्थापक भागीदार के रूप में नई उद्योग-अकादमिक अनुसंधान पहल में शामिल हो गए हैं विज्ञान को

▸▸ केवल प्रकाशनों से आगे बढ़कर समाज के लिए समाधान प्रदान करना चाहिए: डॉ. जितेंद्र सिंह जितेंद्र सिंह

आईआईटी गांधीनगर में "प्रमुख अनुसंधान पहलों की शुरुआत के साथ भारत के विकास की दिशा में अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाना " विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज इस बात पर जोर दिया कि वैज्ञानिक अनुसंधान का वास्तविक मूल्य केवल प्रकाशनों में नहीं है। लेकिन इसमें समाज और अर्थव्यवस्था पर ठोस प्रभाव डालने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत को एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है जहां शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच प्रभावी सहयोग के माध्यम से अनुसंधान प्रयोगशालाओं से सीधे कार्यान्वयन की ओर बढ़े।

मंत्री महोदय ने आईआईटी गांधीनगर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वित्त पोषित "सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी" (सीआईएफ) और तीन नए अनुसंधान क्लस्टरों - एडवांस्ड मैटेरियल्स रिसर्च क्लस्टर (एएमआरसी), एनर्जी रिसर्च क्लस्टर (ईआरसी), और हेल्थकेयर एंड मेडटेक रिसर्च क्लस्टर (उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि लगभग 70 उद्योग संस्थापक भागीदार के रूप में आगे आए हैं, जो उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भौतिक आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत के महत्वपूर्ण निहितार्थों के लिए अनुसंधान प्रकाशनों से परे निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नए लॉन्च किए गए क्लस्टर ट्रांसलेशनल रिसर्च दृष्टिकोण का एहसास करते हैं, जहां वैज्ञानिक खोजों को पायलट विकास में अनुवादित किया जा सकता है। सत्यापन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया जाता है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हाल की विज्ञान नीति पहलों के पीछे मुख्य उद्देश्य अनुसंधान के अवसरों और वित्त पोषण तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय और तकनीकी सहायता उत्कृष्टता के पारंपरिक केंद्रों से परे अन्य संस्थानों तक भी पहुंचे। इसलिए, हमें विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विशेषज्ञता को एक साथ लाकर अपनी विविधता से शक्ति प्राप्त करनी चाहिए।

वर्तमान समय को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दशक बताते हुए मंत्री ने कहा कि भारत तेजी से अग्रणी प्रौद्योगिकियों में एक सक्रिय भागीदार के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और इंडियाएआई मिशन जैसी पहल शोधकर्ताओं और संस्थानों के लिए देश की तकनीकी प्रगति में योगदान करने के नए अवसर पैदा कर रही हैं।

मंत्री ने आईआईटी गांधीनगर में सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी (सीआईएफ) का भी उद्घाटन किया और सीआईएफ पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने साझा वैज्ञानिक ढांचे को नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक बताया, जो शोधकर्ताओं की मदद करेगा। स्टार्टअप और उद्यमों को अत्याधुनिक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है जो व्यक्तिगत संगठनों के लिए स्वतंत्र रूप से स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की रूपरेखा भारत के सेमीकंडक्टर मिशन सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करेगी।

अपनी यात्रा के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईआईटी गांधीनगर रिसर्च पार्क में स्टार्टअप्स और संकाय के नेतृत्व वाली प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों के साथ बातचीत की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से स्थापित, अनुसंधान पार्क नवाचार और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए शोधकर्ताओं , उद्यमियों और उद्योगों के बीच सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।100,000 से अधिक कंपनियों की मेजबानी करता है और 30 से अधिक स्टार्टअप को सहायता प्रदान करता है।

उद्योग की भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने अनुसंधान कार्यक्रमों में उद्योग के साथ शीघ्र जुड़ाव की वकालत की। उन्होंने कहा कि उद्योग के साथ सहयोग अनुसंधान पूरा होने के बाद नहीं बल्कि अवधारणा के चरण में शुरू होना चाहिए, ताकि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण आसान हो जाए और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप हो।

हाल ही में 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। 1 लाख करोड़ रुपये की अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) पहल का उल्लेख करते हुए, मंत्री ने कहा कि यह अनुसंधान और नवाचार में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने संस्थानों और शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और भी अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए उद्योगों और परोपकारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

यात्रा के दौरान, मंत्री ने एनएएमटेक के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक उद्योग-एकीकृत शिक्षण मॉडल के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा विकसित करने के प्रयासों की सराहना की।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2025 के लिए आईआईटी गांधीनगर की शीर्ष 25 अनुसंधान उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाला एक प्रकाशन भी जारी किया। संस्थान के अंतःविषय दृष्टिकोण की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि आईआईटी गांधीनगर सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसने वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने की दिशा में रचनात्मक शिक्षा और अनुसंधान पर जोर देने के साथ अपने लिए एक जगह बनाई है।

अपने सारांश में, मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अनुसंधान समूहों, साझा वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे और उद्योग-एकीकृत नवाचार इकोसिस्टम जैसी पहल भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को मजबूत करेंगी और 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में सार्थक योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि भारत के लिए एक विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग उन संस्थानों द्वारा प्रशस्त किया जाएगा जहां अनुसंधान उद्योग और नवाचार से मिलता है इसे राष्ट्रीय क्षमता में बदलना चाहिए।

गुजरात प्रदेश वाल्मीकि समाज की मांग है कि गुजरात सरकार द्वारा कक्षा 4 के प्रशिक्षुओं की भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात प्रदेश वाल्मीकि समाज की एक बैठक शाम 5:00 बजे न्यू ओपेरा हाउस में भाई लाल बी. वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें वाल्मीकि समाज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया। वाल्मीकि समाज की पढ़ाई के दौरान छात्रों को किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर समाज से संपर्क करने का आह्वान किया गया और यह भी सुनिश्चित किया गया कि वाल्मीकि समाज के युवाओं को रोजगार और रोजगार मिले। यह संकल्प संख्या वित्त विभाग सचिवालय, गांधीनगर, गुजरात सरकार द्वारा जारी किया गया। व्यय संकल्प संख्या 102010-118-जेड.1, दिनांक 14/08/2014 और सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 01/04/2010 के प्रावधानों के अनुसार, चालक तथा श्रेणी-4 चपरासी, चपरासी-सह-चालक, चपरासी-सह-परिचारक, माली, धोबी, चौकीदार, चपरासी-सह-चोकर, सफाईकर्मी, लिफ्टमैन, लिफ्ट परिचारक, सफाईकर्मी, वार्डबॉय, ड्रेसर, नैनी, क्लीनर, ऑपरेशन थिएटर परिचारक, स्ट्रेचर वाहक, पानी वाहक, सहायक, मुखादम, रसोइया, सहायक रसोइया, हमाल, नायक, हवलदार आदि पदों पर भर्ती पर प्रतिबंध है। इस प्रकार, गुजरात राज्य में श्रेणी-4 पदों की भर्ती पर रोक है। जिसके कारण उपरोक्त पदों को राज्य सरकार में लंबे समय से रिक्त रखा गया है। जिसके चलते इन क्षेत्रों में रोजगार की तलाश कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। राज्य सरकार के उपरोक्त प्रस्तावों के कारण पिछले 10 वर्षों से सरकारी अस्पतालों, कॉलेजों आदि जैसे राज्य सरकारी कार्यालयों में भर्ती संभव नहीं हो पाई है। जिसके चलते कई युवा रोजगार से वंचित हैं। सूरत नगर निगम में स्वच्छता कार्य से संबंधित 7000 से अधिक पद पिछले 4 वर्षों से खाली पड़े हैं। जिसके चलते अन्य कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ रहा है।

आज की बैठक में मांग की गई कि राज्य सरकार के उपरोक्त प्रस्तावों को रद्द किया जाए और कक्षा-4 की भर्ती तत्काल की जाए। यदि राज्य सरकार इस मांग पर ध्यान नहीं देती है, तो गुजरात प्रदेश वाल्मीकि समाज द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जाएगी। इस बैठक में भाई लाल वैष्णव, शशिकांत सोलंकी, कांतिभाई सोलंकी, रविभाई सुरती, श्यामभाई तेनिया, गावलेश भगत, सुभाषभाई सोलंकी, जितेंद्रभाई सोलंकी आदि उपस्थित थे। वाल्मीकि समाज की एक बड़ी बैठक 19/06/2026 को सूरत में आयोजित की गई थी।

एक महीने का राज्यव्यापी 'हेलमेट ड्राइव'

हेलमेट नियम का उल्लंघन करने वाले 5,123 सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारियों से 16.58 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया

▸▸ राज्यभर में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुल 1.88 लाख से अधिक मामले दर्ज, 5.21 करोड़ रुपए का जुर्माना

▸▸ जुर्माना वसूलना लक्ष्य नहीं; नागरिकों की जान बचाना हमारा संकल्प है : राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री जी.एस. मलिक

▸▸ ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की राज्य के पुलिस महानिदेशक की अपील

गांधीनगर : सड़क दुर्घटनाओं में कीमती जिंदगियां बचाने और नागरिकों में ट्रैफिक सेंस विकसित करने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में पूरे राज्य में 1 से 31 मई तक एक महीने का विशेष 'हेलमेट ड्राइव' चलाया गया था।

इस विशेष अभियान के बारे में राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री जी.एस. मलिक ने कहा कि जुर्माना वसूलना गुजरात पुलिस का लक्ष्य नहीं है, बल्कि गुजरात के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वाहन चालक और पीछे बैठने वाला व्यक्ति केवल पुलिस के डर से या जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की खुशियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अवश्य पहनें। सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की ही नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। महानिदेशक ने अपील की कि राज्य के सभी नागरिक ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें और जिम्मेदार नागरिक बनें।

सड़क दुर्घटनाओं के अनेक मामलों में यह देखा गया है कि केवल हेलमेट पहनने के कारण वाहन चालक की जान सुरक्षित बच गई। वहीं कई मामलों में "यदि हेलमेट पहना होता, तो आज हमारा प्रिय परिजन जीवित होता..." जैसी आजीवन पीड़ा परिवार को सहन करनी पड़ती है। गुजरात पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी परिवार को ऐसा आघात झेलना पड़े। पुलिस द्वारा समय-समय पर ऐसे अभियान भी चलाए जाते हैं, जिनमें नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के बजाय उन्हें गुलाब का फूल या हेलमेट देकर उसके महत्व के बारे में समझाया जाता है।

इस अभियान के दौरान यह भी साबित किया गया कि ट्रैफिक नियम केवल आम नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए समान हैं। सरकारी कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर ट्रैफिक पुलिस तैनात कर नियमों का उल्लंघन करने वाले 5,123 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए तथा उनसे 16.58 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।

स्टेट ट्रैफिक ब्रांच द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्यभर में चलाए गए इस अभियान के दौरान सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों सहित कुल 1.88 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए और 5.21 करोड़ रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई।

नासिरनगर विध्वंस मामला: जांच समिति पर सवाल, दोषियों के खिलाफ पुलिस शिकायत की मांग

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के नासिर नगर में हुए रहस्यमय विध्वंस की जांच के लिए नगर आयुक्त नागराजन द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। यह मामला राज्य और देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उप नगर आयुक्त मीना गजजर की अध्यक्षता में गठित यह समिति अब इस पूरे मामले के विभिन्न पहलुओं की चरणबद्ध जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही इस विवादित विध्वंस मामले में शामिल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

इस जांच समिति में मीना गज्जर, उप नगर आयुक्त मनीष डॉक्टर, अतिरिक्त नगर अभियंता महेश चावड़ा, कार्यकारी अभियंता केएल वासावा, आर डी गंजावाला और उप अभियंता मोहसिन कागजी शामिल हैं। इस समिति में आवश्यक साक्ष्यों सहित सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और अंतिम रिपोर्ट नगर आयुक्त को सौंपी जाएगी। इस तरह, सूरत नगर निगम प्रशासन और अधिकारियों के लिए सिरदर्द बने नासिर नगर के जीर्ण-शीर्ण विध्वंस मामले में विधायक विनू मोर्डिया ने अब अपनी बात रखी है। विनू मोर्डिया ने नगर निगम की जांच समिति पर भी संदेह जताया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या नगर निगम के अधिकारी खुद अपने सहयोगियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। उन्होंने (विनूभाई) आगे कहा कि इस पूरे मामले की जांच सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इस प्रकार, जब पिछले दस दिनों से इन 150 कच्चे और अधूरे मकानों के विध्वंस का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, तो जांच समिति पर उठ रहे सवाल भी उतनी ही समस्या पैदा कर रहे हैं।

अब, विनू मोर्डिया ने भाजपा विधायक द्वारा गठित नगर निगम की जांच समिति का विरोध करने के साथ-साथ पूरे मामले के दोषियों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने की भी मांग की और उनसे निकट भविष्य में गांधीनगर में इस मामले पर एक प्रस्तुति देने को कहा।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सूरत हवाई अड्डे के आसपास एक निश्चित किलोमीटर क्षेत्र में ऊंची इमारतें बनाना अपराध है। ऐसी इमारतों को गिराने के नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, अदालती मामलों के कारण वे इमारतें अब भी सुरक्षित खड़ी हैं और हवाई अड्डे पर आने वाले विमानों के लिए खतरा बनी हुई हैं। यदि ऊंची इमारतों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो नासिर नगर जैसे गरीब लोगों के 150 मिट्टी की ईंटों से बने मकान बिना नोटिस के कैसे गिरा दिए गए? यह सवाल आज भी शहरवासियों के मन में गूंज रहा है।